



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 2013/पौष 24, 1934

No. 12]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 2013/PAUSA 24, 1934

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 14 जनवरी, 2013

सं. टीएएमपी/37/2007-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा कांडला पत्तन न्यास (केडीएलबी) के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग की लेवी तथा अन्य प्रभारों के बदले ऑन-बोर्ड श्रमिकों की प्रचलित सम्मिश्र दर की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/37/2007-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास

.....

आवेदक

गणपूर्ति :

- (i) श्रीमती रानी जाधव, अध्यक्ष
- (ii) श्री टी. एस. बालासुब्रामण्यन, सदस्य (वित्त)

आदेश

(दिसम्बर, 2012 के 17वें दिन पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास (केडीएलबी) के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग की लेवी तथा अन्य प्रभारों के बदले ऑन-बोर्ड श्रमिकों की प्रचलित सम्मिश्र दर की वैधता विस्तारित करने से संबंधित है।

2.1 इस प्राधिकरण ने कांडला पत्तन न्यास के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के अन्य प्रभारों की लेवी के बदले 31 मार्च 2012 तक एक वर्ष की अवधि के लिए, जहाज पर तैनात श्रमिकों के लिए वस्तुवार प्रतिटन आधार पर सम्मिश्र दर तय करने हेतु कांडला पत्तन न्यास के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए आदेश सं. टीएएमपी/37/2007-केपीटी दिनांक 25 मार्च 2011 पारित किया था। ये प्रभार केपीटी के दरमान के अध्याय-III में धारा-3 के रूप में शामिल किये गए थे। यह आदेश भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-III खंड 4) में राजपत्र सं. 94 के माध्यम से 5 मई 2011 को अधिसूचित किया गया था।

2.2 तत्पश्चात्, केपीटी के अनुरोधानुसार, इस प्राधिकरण ने दिनांक 9 अप्रैल 2012 को कार्गो प्रहस्तन प्रभाग की ऑन-बोर्ड श्रमिकों की प्रचलित सम्मिश्र दर की वैधता 31 मार्च 2012 से आगे 30 जून 2012 तक विस्तारित करने हेतु एक आदेश पारित किया था। इस आदेश को भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-III खंड 4) राजपत्र संख्या 107 के माध्यम से 25 अप्रैल 2012 को अधिसूचित किया गया था। पुनः केपीटी के अनुरोधानुसार, इस प्राधिकरण ने दिनांक 8 अगस्त 2012 को कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के ऑन-बोर्ड श्रमिकों की प्रचलित सम्मिश्र दर की वैधता 30 जून 2012 से आगे 31 अक्टूबर 2012 तक विस्तारित करने हेतु एक आदेश पारित किया था। इस आदेश को भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-III खंड 4) राजपत्र संख्या 182 के माध्यम से 29 अगस्त 2012 को अधिसूचित किया गया था। प्राधिकरण ने कार्गो प्रहस्तन प्रभाग की लेवी तथा अन्य प्रभारों के बदले ऑन-बोर्ड श्रमिकों की प्रचलित सम्मिश्र दर की वैधता 31 मार्च 2012 से आगे इस शर्त पर विस्तारित की थी कि विस्तारित अवधि के दौरान, यदि कोई, अतिरिक्त अधिशेष केपीटी को प्रोद्भूत होता है तो उसे निर्धारित होनेवाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा।

3.1 केपीटी ने कार्गो प्रहस्तन प्रभाग की लेवी तथा अन्य प्रभारों के बदले ऑन-बोर्ड श्रमिकों की प्रचलित सम्मिश्र दर के प्रस्ताव को अपने पत्र दिनांक 6 जून 2012 के द्वारा प्रस्तुत किया है। केपीटी के प्रस्ताव को संबंधित उपयोगकर्ताओं के परामर्श के लिए रखा गया है। केपीटी का प्रस्ताव संवीक्षा के अधीन था और हम ने केपीटी से अपने पत्र सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी दिनांक 08 अक्टूबर 2012 के माध्यम से स्पष्टीकरण/सूचना की मांग की है। केपीटी के प्रत्युत्तर अभी प्रतीक्षित हैं।

3.2 गुजरात राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो चुकी है। केपीटी ने कहा है कि संयुक्त सुनवाई के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेगा और हमें सूचित करेगा। इसलिए, दिनांक 19 अक्टूबर 2012 को होनेवाली संयुक्त सुनवाई को वापस ली गई थी। इस संबंध में, केपीटी का प्रत्युत्तर अभी प्रतीक्षित है।

4. इस पृष्ठभूमि में, केपीटी ने गुजरात में होनेवाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता का हवाला देते हुए, दिनांक 31 अक्टूबर 2012 के अपने पत्र सं. एफए/कॉस्ट/1021-सीएचडी/254 के माध्यम से कहा है कि चूँकि दर अनुमोदन के लिए अभी कुछ और समय लागेगा, इसने, प्राधिकरण द्वारा दर अनुमोदित किये जाने तक की अवधि के लिए, ऑन-बोर्ड श्रमिकों की सम्मिश्र प्रचलित दर से वसूली करने हेतु, अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

5. विस्तारित दर की वैधता को पहले ही 31 अक्टूबर 2012 समाप्त हो चुकी है। ऑन-बोर्ड श्रमिकों की प्रचलित सम्मिश्र दर के प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित करना अभी बाकी है। इन सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस प्राधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से विचार किये जाने हेतु इस मामले को परिपक्व होने में कुछ और समय लगेगा। इसलिए, कांडला पत्तन न्यास के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग की लेवी तथा अन्य प्रभारों के बदले ऑन-बोर्ड श्रमिकों की (प्रचलित) सम्मिश्र दर की वैधता 31 अक्टूबर 2012 से आगे विस्तारित करना आवश्यक हो गया है।

6. इसलिए यह प्राधिकरण कांडला पत्तन न्यास के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग की लेवी तथा अन्य प्रभारों के बदले ऑन-बोर्ड श्रमिकों की प्रचलित सम्मिश्र दर की वैधता 31 अक्टूबर 2012 से आगे 28 फरवरी 2013 तक अथवा कार्गो प्रहस्तन प्रभाग की लेवी तथा अन्य प्रभारों के बदले ऑन-बोर्ड श्रमिकों की संशोधित सम्मिश्र दर की प्रभावी कार्यान्वयन तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित की जाती है। किंतु दरों की वैधता का यह विस्तार उस शर्त के अधीन है कि यदि कोई अधिशेष वैधता की विस्तारीत अवधि में केपीटी के पास जमा होता है वह निर्धारित होने वाले प्रशुल्क में पूरा समायोजित किया जाएगा, की अवधि जैसा दरों की वैधता 31 मार्च 2012 से आगे विस्तारीत करते हुए अनुबंधित किया गया था।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/12/असाधारण]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th January, 2013

No. TAMP/37/2007-KPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing composite rate for on-board labour in lieu of levy and Other charges of cargo Handling Division of Kandla Port Trust (KDLB) as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/37/2007-KPT

Kandla Port Trust

.....

Applicant

QUORUM:

- (i) Smt. Rani Jadhav, Chairperson
- (ii) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)

ORDER

(Passed on 17th day of December, 2012)

This case deals with the extension of the validity of the existing composite rate for on-board labour in lieu of levy & other charges of Cargo Handling Division of Kandla Port Trust (KDLB).

2.1. This Authority had passed an Order No. TAMP/37/2007-KPT dated 25 March 2011 approving the proposal of Kandla Port Trust (KPT) to fix the composite rate for on-board labour in lieu of levy of other charges of its cargo handling division on a commodity wise per tonne basis for a period of one year i.e.

upto 31 March 2012. The charges were incorporated as clause 3 in Chapter III of the KPT's Scale of Rates. This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 5 May 2011 vide Gazette No. 94.

2.2. Thereafter, based on the request of KPT, this Authority has passed an Order dated 9 April 2012 extending the validity of composite rate for on-board labour beyond 31 March 2012 upto 30 June 2012. This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 25 April 2012 vide Gazette No.107. Again, based on the request made by KPT, this Authority vide its Order dated 8 August 2012 has extended the validity of composite rate for on-board labour beyond 30 June 2012 upto 31 October 2012. This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 29 August 2012 vide Gazette No.182. The extension of validity of composite rate for on-board labour beyond 31 March 2012 has been granted subject to the condition that the additional surplus, if any, that may accrue to KPT beyond 31 March 2012 will be adjusted fully in the tariff to be fixed.

3.1. The KPT vide its letter dated 6 June 2012 has submitted the proposal for fixation of composite rate for on-board labour in lieu of levy and other charges of Cargo Handling Division. The proposal of KPT has been taken on consultation with the relevant users. The proposal of the KPT was subjected to scrutiny and we have vide our letter no.TAMP/41/2012-KPT dated 8 October 2012 sought additional information/ clarification from KPT. The response of KPT is awaited.

3.2. On account of the upcoming General Elections for the Legislative Assembly of Gujarat State Code of Conduct has come into force. KPT has stated that it would approach the Election Commission (EC) seeking permission from EC for holding the joint hearing and communicate the same to us. Therefore, the joint hearing scheduled on 19 October 2012 was called off. The response of the KPT in this regard is awaited.

4. In this backdrop, the KPT vide its letter no.FA/COST/1021-CHD/254 dated 31 October 2012 by referring to the code of conduct of forthcoming Assembly Election in Gujarat, has stated that since it will take some time for approval of rates, it has requested to allow it to collect the existing composite rate for on-board labour for a further period till the rates are approved by this Authority.

5. Considering that the extended validity of the rates has already expired on 31 October 2012 and that the joint hearing on the proposal of fixation of composite rate for on-board labour is yet to be re-fixed and taking into account the position that thereafter, it may take some more time for the case to mature for final consideration of this Authority, it is necessary to extend the validity of the composite rate for on-board labour in lieu of levy and other charges of Cargo Handling Division of Kandla Port Trust beyond 31 October 2012.

6. This Authority, therefore, extends the validity of the rates for on-board labour beyond 31 October 2012 up to 28 February 2013 or till the effective date of implementation of the revised composite rate for on board labour in lieu of levy and other charges of Cargo Handling Division, whichever is earlier. However,

the extension of validity of rates is subject to the condition that the additional surplus, if any, that may accrue to KPT during the extended period of validity will be adjusted fully in the tariff to be fixed, as stipulated at the time of extension of validity of the rates beyond 31 March 2012.

RANI JADHAV, Chairperson
[ADVT. III/4/143/12/Exty.]

21541/13-2